सम्पादक के नाम

राज्यवर्धन राठौड़ तक कोई मेरा यह पत्र पहुंचा दे प्लीज़

माननीय राज्यवर्धन राठौड़ जी,

आपका एक नया वीडियो देख रहा हूं जिसमें आप भारत सरकार के कार्यालय में पुश अप कर रहे हैं। उम्मीद है आपके मंत्रालय के सचिव, निदेशक और सभी कर्मचारी काम छोड़ कर पुश अप कर रहे होंगे। बिना काम छोड़े पुश अप तो हो नहीं सकता। मैं जानना चाहता हूं कि जो चैलेंज आप दूसरों को दे रहे हैं, उसकी आपके मंत्रालय के भीतर क्या स्थिति है? क्या वे आपको देखते ही पुश अप करने लग जाते हैं या आप आते हैं तो अपने पुश अप का वीडियो बनाकर दिखा देते हैं। सचिव जी क्या कर रहे हैं, उन्हें भी कहिए कि पुश अप कर ट्विट करें। क्या यह अच्छा रहेगा कि कुछ डाक्टरों और जिम ट्रेनर की टीम आपके मंत्रालय के कर्मियों की स्वास्थ्य समीक्षा करे।

ये जो आप पुश अप कर रहे हैं वो योग के किस आसन के तहत आता है? सूर्यनमस्कार में भी दंड पेलने की एक संक्षिप्त मुद्रा है और भुजंगासन भी इसका समानार्थी है। पर्वतासन में भी आता है और मुमकिन है कि इसका एक स्वतंत्र आसन भी होगा। लेकिन मंत्री जी आप जिस तरह चमड़े के जूते और कसी हुई कम मोहरी वाली पतलून में पुश अप कर रहे हैं वह कत्तई भारतीय नहीं है। हमने अमर चित्र कथा में दंड पेलने की तमाम तस्वीरें देखी हैं। उनमें दंड पेलने वाले धोती पहना करते हैं। आप शायद नए ज़माने के हैं इसलिए आफिस की महंगी कालीन पर दंड पेल रहे हैं, वैसे इसकी जगह मिट्टी की ज़मीन है। जहां हमारे पहलवान भाई रोज़ मिट्टी आंख मुंह में पोत कर दंड पेलते हैं। आपकी तरह भारत के लिए पदक जीत लेते हैं।

विगत चार साल से भारत सरकार और व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री मोदी योग के प्रचार पर काफी ध्यान दे रहे हैं। इतना कि 2014 से पहले मीडिया में योग रामदेव के कारण जाना जाता था, अब रामदेव जी भी योग के कारण कम इनदिनों बिजनेस टायकून होने के कारण ज़्यादा जाने जा रहे हैं। शायद वे भी नहीं चाहते होंगे कि योग के ब्रांड अंबेसडर को लेकर किसी से टकराव हो और उसका उनके व्यापार पर असर पड़े। इसलिए उन्होंने योग का मैदान प्रधानमंत्री के हवाले कर दिया है। योग का प्रचार कोई भी करे इससे रामदेव को कभी एतराज़ भी नहीं रहा है।

आपने अचानक यूरोपीय शैली में पुश अप को क्यों प्रचारित किया? इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं, उसमें भारतीयता तो है। लेकिन संसद में आपके सहयोगी और मेरे मित्र मनोज तिवारी क्या कर रहे हैं? पुश अप विधा का विकास कर रहे हैं या विकृति पैदा कर रहे हैं? आप भी उनका वीडियो देखिए। पुश अप करने के बाद मनोज तिवारी अचानक उसके जैसा कूदने फांदने लगते हैं जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता। जब देश में पेट्रोल के दाम 85 रुपये प्रति लीटर पार कर गए हों, हाहाकार मचा हो, तब मनोज तिवारी का पुश अप के बाद अफ्रीकी मूल का नृत्य मुझे अच्छा नहीं लगा। इससे मेरा भारतीय मन आहत हुआ है।

आपको पता होगा कि प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत का स्थान पिछले साल से दो पायदान नीचे चला गया है। भारत 136 से 138 पर आ गया है। 137 पर म्यानमार है। 139 पर पाकिस्तान है। इसमें आपके मंत्रालय की क्या जिम्मेदारी बनती है, इस पर बहस हो सकती है लेकिन जिस मुल्क में प्रेस की स्वतंत्रता की ये हालत हो, उस ग़रीब मुल्क का सूचना प्रसारण मंत्री अपने आलीशान दफ्तर में पुश अप करे, थोड़ा उचित नहीं लगा। आपने इस तरह की रैंकिंग आने के बाद सुधार के लिए कोई बैठक बुलाई है? आपकी पूर्व सहयोगी स्मृति ईरानी ने फेक न्यूज़ के नाम पर मीडिया पर जो बंदिश लगाने की कोशिश की थी, उससे उन्हें हटना पड़ा था। इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि प्रेस की स्वतंत्रता का माहौल बना रहे, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं।

कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने एक झूठ बोला कि किसी कांग्रेस नेता ने जेल में शहीद भगत सिंह से मुलाकात नहीं की। उन्होंने कहा कि कोई जानकारी देगा तो वे सुधार करने के लिए तैयार हैं। क्या सूचना व प्रसारण मंत्री के रूप में आपका दायित्व नहीं बनता कि प्रधानमंत्री की तरफ से आप देश को बताएं कि सही जानकारी यह है कि नेहरू ने ही जेल में भगत सिंह से मुलाकात की थी।

आप प्रधानमंत्री से इतनी ऊर्जा पा रहे हैं कि दफ्तर में ही पुश अप करने का ख़्याल आ जाता है। यह अच्छा है। मगर सही सूचना के प्रति आपकी क्या ज़िम्मेदारी है? क्या आपने वो ज़िम्मेदारी निभाई? क्या आपके मंत्रालय ने दूरदर्शन पर चलाया कि प्रधानमंत्री से एक चूक हुई है। नेहरू ने भगत सिंह से जेल में मुलाकात की थी।

मैं नहीं चाहता कि आप इस बात से शर्मिंदा हो कि जन स्वास्थ्य के मामले में भारत की रैंकिंग उतनी ही ख़राब है जितनी प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में। दुनिया के 195 देशों में भारत का स्थान 145 वें नंबर है। चार साल में इसे ठीक करने की उम्मीद भी नहीं रखता मगर मैं चाहता हूं कि आप एम्स को लेकर संसदीय समिति की जो रिपोर्ट आई है, उसे ही पढ़ लें। अब जब आप अपना काम छोड़कर स्वास्थ्य मंत्री का काम कर ही रहे हैं तो यह भी जान लें। भारत के 6 एम्स में पढ़ाने वाले डॉक्टर प्रोफेसर के 60 फीसदी पद खाली हैं। नॉन फैकल्टी के 80 फीसदी से अधिक पद ख़ाली हैं। 18,000 से अधिक पदों पर अगर चार साल में नियुक्ति हो गई होती तो आज कितने ही युवाओं के घर में खुशियां मन रही होती। वे भी पुश अप कर रहे होते। बेरोज़गारी में आपकी तरह पुश अप करने से आंत बाहर आ जाएगी। आपकी जो फिटनेस है वो सिर्फ पुश अप से नहीं है बल्कि डाइट से भी है।

आप मंत्री हैं। सांसद हैं। ज़रूर सांसदों को हंसी मज़ाक या हल्का फुल्का आचरण करने की छूट होनी चाहिए मगर जनप्रतिनिधि की एक मर्यादा होती है। वो इन मर्यादाओं से बंधा होता है। हम समझते हैं कि आप कुछ लोकप्रिय लोगों को चैलेंज देकर युवाओं को प्रेरित करना चाहते हैं। भारत का युवा जानता है कि उसे हेल्थ के लिए क्या करना है। जिसके पास पैसे हैं और जो जिम जा सकता है, वो जा रहा है। दो चार युवा होते हैं जो अजय देवगन और शाहरूख़ ख़ान की तरह दिखने लगते हैं, बोलने लगते हैं और चलने लगते हैं। मुमकिन है कि दो चार आपकी तरह देखने बोलने और चलने लगें लेकिन यह सोचना कि युवाओं की मानसिकता ही यही होती है, उनके साथ नाइंसाफी होगी। क्या यह अच्छा नहीं होता कि 100 से अधिक जिन बच्चों ने एस सी एस की परीक्षा पास कर आपके मंत्रालय से नियुक्ति पत्र का इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी आप ज्वाइनिंग करा दें। उम्मीद हैं आप सोमवार तक इन्हें नियुक्ति पत्र दे देंगे परीक्षा पास कर दस महीने से ये लड़के इंतज़ार कर रहे हैं और आप नौजवानों को पुश अप करने का वीडियो दिखा रहे हैं यह उचित हो सकता है मगर बकौल रवीश सर्वथा अनुचित है। वैसे आप ये पतलून और शूट सिलाते कहां हैं, डिज़ाइनर है कोई या शाहदरा का कोई टेलर है। बाकी सवाल का जवाब दे या न दें, मुझे टेलर का पता दे दीजिएगा मंत्री जी। मुझे भी हैंडसम दिखने का मन कर रहा है। लगे हाथ इंडिया भी फिट हो जाएगा, ऐसा योगदान मेरा भी हो जाए, भक्त भी खुश हो जाएंगे।

आपका, रवीश कुमार,
दुनिया का पहला ज़ीरो टीआरपी एंकर

समाज रूपी गंगा दूषित हो चुकी तो पत्रकारिता उसी से निकली नहर है

फेसबुक पर ही कहीं किसी लेख को पढ़ते हुए देखा वहाँ लिखा था पत्रकारिता जैसा पवित्र कार्य भी अब विश्वसनीयता खो रहा है तब लगा कि-

जिस देश में सर्वाधिक विश्वास करने योग्य न्यायपालिका अपने ही किसी जज की हत्या को छिपाने के लिए बिक जाए...

जहाँ अत्यधिक तनख्वाह पाने के बावजूद और पैसों की वृद्धि को लेकर डॉक्टर अपने मरीजों को मरता छोड़ हड़ताल पर चले जाए... जहाँ नौकरी लगने या लगवाने के लिए खुले आम रिश्वत दी और ली जाए...

जहाँ स्कूल-कॉलेज, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए नहीं बल्कि पैसा कमाने के लिए खोले जाए...

जहाँ अध्यापक कक्षाओं में नहीं कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ाएँ...

जहाँ सरपंच, एम.एल.ए, मंत्री, महामंत्री, प्रधानमंत्री आम- जनता को हर बार लूट कर आत्महत्या करने पर मजबूर करते जाए... जहाँ स्त्री को देवी का दर्जा देकर उसका बलात्कार किया जाए और बलात्कारियों के पक्ष में जूलूस निकाला जाए...

और तो और जहाँ धर्म या मजहब के नाम पर किसी भी बेगुनाह की बेखौफ हत्या कर दी जाए....

उस देश में मात्र पत्रकारिता से पवित्रता की उम्मीद करना

रेत के ढेर में से सोना निकलने की उम्मीद करना है।

- नेहा

ईस्टर्न पेरीफेरल वे के लिए गडकरी जी की पीठ थपथपाई

ईस्टर्न पेरीफेरल वे के लिए गडकरी जी की पीठ थपथपाई जा रही है, मोदी जी विकास के दावे किए जा रहे हैं, हाइवे में सोलर से लाइट जलेगी, इतने महीनो में हाइवे बना दिया आदि आदि। चलिए गडकरी के मंत्रालय के कामकाज की हकीकत जान लीजिए। जिन दोनों सड़को का मोदीजी ने उदघाटन किया उसके बारे में ही सरकार कह रही है कि वह विलम्ब से पूरा हुआ है। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे को निर्धारित तिथि पर पूरा करने में विफलता के कारण ही एनएचएआइ के सीएमडी दीपक कुमार तथा मेंबर-फाइनेंस रोहित कुमार सिंह का तबादला किया गया था।

पिछले दिनों में सरकार ने लोकसभा में दिए गए जवाब के अनुसार मार्च, 2018 तक कुल 107 सड़क परियोजनाएं समय से पीछे चल रही थीं। इनमें मई 2014 से अगस्त, 2016 के दौरान शुरू की गई 19 परियोजनाएं शामिल हैं। आम तौर पर कोई सड़क परियोजना ढाई-तीन साल में पूरी हो जाती है। परंतु कुछ मामलों में अभी भी चार साल तक का समय लग रहा है।

- साइबर नजर

भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए जनान्दोलन जरूरी

मनोज कुमार झा

अगले वर्ष लोकसभा चुनाव होने हैं। अभी हाल में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो बुरी हालत हुई, उससे साफ पता चलता है कि आगे उसका भविष्य क्या है। चार साल के शासन के दौरान हर मोर्चे पर विफल रहने के साथ ही पूरी तरह बदनाम हो चुकी इस पार्टी का सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार व औचित्य नहीं रह गया है, पर भाजपा का यदि नैतिकता से कोई लेना-देना रहता तो यह दो दिन के लिए कर्नाटक में सरकार बना कर अपनी किरकिरी नहीं करवाती। यह तो कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों ने सूझबूझ के साथ तत्काल काम किया और भाजपा को बहुत बेआबरू हो कर कर्नाटक की कुर्सी छोड़नी पड़ी।

बहरहाल, इस साल राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां भाजपा और भाजपा-विरोधी दलों की ताकत का सही अंदाज लग सकेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों में भाजपा की हालत बुरी है। हर वर्ग के लोग भाजपा के शासन से त्रस्त हो चुके हैं और किसी भी हाल में इसे सत्ता में देखना नहीं चाहते। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की हालत खराब है। यह माना जा रहा है कि भाजपा वहां मुख्यमंत्री पद के लिए कोई दूसरा चेहरा तलाश रही है, पर किसे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने लाए, यह भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रणनीतिकारों की समझ में नहीं आ रहा है। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि शिवराज पूरी कोशिश में लगे हैं कि मुख्यमंत्री पद उनकी ही झोली में रहे, पर पार्टी और संघ के दिग्गज नेता इसके लिए तैयार नहीं हैं।

यही हाल राजस्थान में है। वसुंधरा राजे को भाजपा के कई नेता सख्त नापसंद करते हैं। वहां कोशिश की जा रही है कि किसी अन्य नेता को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर चुनाव में उतरा जाए, पर किसी नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। वहीं, कांग्रेस ने इस दिशा में कुछ कदम बढ़ाये हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को कमान सौंप दी गई है। कहा जा रहा है कि कमलनाथ चुनावी शतरंज की बिसात पर नयी चालें चलेंगे। बहरहाल, इन दो राज्यों में जो चुनाव-परिणाम आएंगे, उनका आगामी लोकसभा चुनाव पर असर पड़ना तय है। माना जा रहा है कि कर्नाटक से भाजपा के पतन की शुरुआत हो चुकी है।

कर्नाटक में कांग्रेस के गठबंधन में जनता दल (सेक्युलर) के नेता एच.डी. कुमारस्वामी की सरकार बनने से विरोधी दलों में नया उत्साह आया है। उस मौके पर तमाम विरोधी दलों के नेताओं के एक मंच पर आने से यह उम्मीद जगी है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के विरुद्ध एक मजबूत गठबंधन बन सकता है। इस गठबंधन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल आदि के साथ आने की संभावना दिख रही है। इस मौके पर सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी भी नजर आए थे। माना जा रहा है कि सीपीएम भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल हो सकती है। पर पश्चिम बंगाल में तृणमूल के साथ उसका छत्तीस का जो आंकड़ा है, उसे देखते हुए गठबंधन में शामिल होने पर संदेह भी जताया जा रहा है। जो भी हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि वामपंथी दल भाजपा-विरोधी गठबंधन में शामिल नहीं होते, तो उनके राजनीतिक अस्तित्व पर सवालिया निशान लग जाएंगे। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में वामपंथी दल पूरी तरह से कटे-कटे नजर आ रहे हैं। इस पर वाम नेताओं को गंभीर विचार-मंथन की जरूरत है।

दूसरी सबसे महत्त्वपूर्ण जो बात है, वह यह कि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा- विरोधी दलों को अभी से ही गठबंधन बनाने का प्रयास तेज कर देना चाहिए और साथ ही भाजपा सरकार की नीतियों को लेकर आंदोलनात्मक गतिविधियां भी शुरू कर देनी चाहिए। इससे जनता में इनकी पैठ बढ़ेगी। सिर्फ चुनावी रणनीति बनाने से काम नहीं चलने वाला। जनता के बीच जाकर संपर्क करना और स्थानीय स्तर पर लोगों को जोड़ना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए सभी दलों को अपने स्तर पर सक्रियता दिखानी होगी। इसमें कांग्रेस की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। भूलना नहीं होगा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर सिर्फ कांग्रेस और उसके नेता ही रहते आए हैं।

हाल के दिनों में नरेंद्र मोदी ने पं. जवाहरलाल नेहरू को लेकर काफी दुष्प्रचार किया है, जिससे लोगों में गुस्सा है। कांग्रेस को विकास और अन्य मुद्दों को लेकर जनता से हर स्तर पर संवाद कायम करना चाहिए, तभी कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आ सकता है। चूंकि भाजपा के बरक्स कांग्रेस ही एकमात्र सबसे बड़ा दल है, इसलिए स्वाभाविक है कि उसके नेतृत्व में ही गठबंधन बन सकता है। पर कांग्रेस को जिस आक्रामकता के साथ आने वाले चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए था, वैसा वह कर नहीं पा रही है। राहुल गांधी का जनता से संवाद कायम नहीं हो पा रहा है। राजनीतिक मंच पर लगातार उनकी मौजूदगी दर्ज नहीं हो पा रही है। ऐसे में, संशय की स्थिति बनती है।

कांग्रेस नेतृत्व को यह समझ लेना चाहिए कि पहले की नीतियों पर चल कर उसे सफलता नहीं मिल सकती। चुनाव मैनेजरों के सहारे चुनाव जीत पाना संभव नहीं हो सकता। उसे उत्तर प्रदेश में अपने हश्र को देखना चाहिए, जहां मूर्खतापूर्ण खटिया सभाओं में उसकी खटिया खड़ी हो गई थी। जनता का विश्वास जीतने के लिए आंदोलनात्मक गतिविधि चलाना ही एकमात्र विकल्प है। आंदोलनात्मक गतिविधियों के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विरोधी दल जनता के बीच जा सकते हैं और राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य, जिला और पंचायत स्तर पर आंदोलन खड़ा कर उनमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। कांग्रेस और दूसरे दलों को जनता की शक्ति में भरोसा करना होगा। जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए उसके बीच जाना ही एकमात्र उपाय है, अन्यथा अंत में हाथ मलने के सिवा और कुछ भी नहीं बचेगा। भाजपा साजिशों और तिकड़म के बल पर चुनाव जीतती रही है। उसके पास धनबल भी है। दिखावे की नैतिकता में भी भाजपा को यकीन नहीं है। इसलिए कांग्रेस और अन्य दलों को यह समझना होगा कि व्यापक जनसमर्थन से ही वे भाजपा को 2019 में सत्ता में आने से रोक सकते हैं।